# कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक–03.08.2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
पौड़ी।

**विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग में केदारनाथ के विकासखण्ड़ अगस्त्यमुनि मणिगुह मोटर मार्ग से स्याल डोभा होते हुये खाली–खमोली तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/16066/2015)**

महोदय,

प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा दी गयी बिन्दुओं पर सूचना माँगी गई थी। परन्तु आपके स्तर से उन इन बिन्दुओ के स्थान पर कुछ और ही सूचना आनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। इस समबन्ध में सूचित करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पार्ट ।। में सही सूचना अपलोड़ करे बिना ही प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा रहा है। जिसके क्रम में उक्त प्रकरण को इस कार्यालय द्वारा सूचना पूर्ण रूप से दिये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा बार बार वापस लोटाया जा चुका है। परन्तु फिर भी न तो प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी एवं आपके द्वारा इस और ध्यान न देकर मात्र एक औपचारिक्ता निभाते हुए सूचना इस कार्यालय का अग्रेसारित की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है, कि भारत सरकार द्वरा ऐसे प्रकरणों की सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रकरणो को वापस लौटाया जा रहा है।

अतः भविष्य में यह सुनिचित किया जाए की भारत सरकार/इस कार्यालय द्वारा वान्छित बिन्दुओं की पूर्ण बिन्दुवार सूचना उपरोक्त उलिखित के अनुसार ही इस कार्यालय अग्रसारित करने का कष्ट करे। भारत सरकार द्वारा वान्छित सूचना पुनः संलग्न की जा रही है।

| SR.No | भारत सरकार द्वारा लगायी गई आपत्ति | प्राप्त आपत्ति निराकरण के जॉच के बाद पायी गयी कमियॉ |
|---|---|---|
| 1 | Component wise break up is not provided in online Part I.the component wise break up should include area marked for various component viz road muck dispoal etc. | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्या आनलाईन भरी गई सूचना के अनुरूप नही है, कृप्या सही सूचना आनलाईन अपलोड़ करना सुनिश्चित करें। |
| 2 | The village wise breakup is not clear as the details provided with the proposal of villages to be benefited are of 5 villagers but in village wise break up details furnished only two villages and the area of forest land is also not mentioned against these two villages, The State Govt may review the same and provide correct details for each villages in village wise breakup in online Part I. | प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा बताई गयी सूचना भारत सरकार से चाही गयी सूचना के अनुरूप नही है। |
| 3 | As per the villages to be benefited by the proposal includes 5 villagers but the village level committee proceedings provide pertaining to only one village . the State Govt may review the same and clarify accordingly. if required provided the VLC proceedings for other villages also. | प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा बताई गयी सूचना भारत सरकार से चाही गयी सूचना के अनुरूप नही है। |